सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 79 — दर्ज तिथिः–15.02.2024

1. गंगाराम पुत्र कानाराम
2. भागीरथराम पुत्र कानाराम
3. सेनाराम पुत्र कानाराम

जाति विश्नोई निवासी सिंधासवा चौहान पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुडामालानी
.................वादी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान पंचायत समिति गुडामालानी
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान

.................असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार गुडामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हरिराम विश्नोई
अप्रार्थीः–श्री हरीश चौधरी

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रकिया संहिता–1908

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.10.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के तहत हाजा न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण जबरदस्ती सीसीरोड व सडक बना रहे है। प्रतिवादीगण कटान मार्ग से हटकर वादी की खातेदारी आराजी में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सडक निर्माण कर रहे है। इससे वादी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अतः प्रतिवादीगण को कटान मार्ग से हटकर वादी की खातेदारी आराजी में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सडक निर्माण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के

अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया—

- कि वाद वर्णित आराजी 176/16, 176/18 मौजा सिंधासवा चौहान ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान के खाते में दर्ज रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आराजी है। जिससे वादीगण का कोई हित नहीं है। ग्राम पंचायत की आराजी पर वादी को स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। असल में वादी द्वारा ग्राम पंचायत की उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है।
- दावे में वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 के तहत सरकारी संस्था ग्राम पंचायत को बिना नोटिस दिये हस्तगत वाद दायर किया है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 के तहत सरकारी संस्था को दो माह का नोटिस देना आवश्यक कानूनी बाध्यता है। उक्त कानूनी बाध्यता की पालना नहीं होने पर दावा विधि द्वारा वर्जित है। अतः वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिले—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थी/प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया—

- कि वादपत्र में वर्णित वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण जबरदस्ती सीसीरोड व सडक बना रहे है। प्रतिवादीगण कटान मार्ग से हटकर वादी की खातेदारी आराजी में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सडक निर्माण कर रहे है। इससे वादी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अतः वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***11. Rejection of plaint.***- *The plaint shall be rejected in the following cases:—*
> *(a) where it does not disclose a cause of action;*
> *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;*
> *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
> *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;*
> *(e) where it is not filed in duplicate;*
> *(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of Rule 9.*
>
> ***Provided that*** *the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

> *cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

5. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः—

> While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.

6. सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैंः—

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविक्ता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरूस्त नहीं करना।
3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरूस्त नहीं करना।
4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद—पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

Object

7. सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के **उद्देश्य** (Object) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519 / 2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation, so that further judicial time is not wasted.*

8. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका उनवान Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi में दिनांक 25.07.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The whole purpose of conferment of such powers is to ensure that a litigation which is meaningless and bound to prove*

Signature Not Verified
Digitally Signed by Keshav Kumar
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

> *<u>abortive should not be permitted to occupy the time of the court and exercise the mind of the respondent.</u> The sword of Damocle need not be kept hanging over his head unnecessarily without point or purpose. Even in an ordinary Civil litigation the Court readily exercises the power to reject a plaint if it does not disclose any cause of action. Or the power to direct the concerned party to strike out unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious parts of the pleadings. Or such pleadings which are likely to cause embarrassment or delay the fair trial of the action or which is otherwise an abuse of the process of law. An order directing a party to strike out a part of the pleading would result in the termination of the case arising in the context of the said pleading. The Courts in exercise of the powers under the Code of Civil Procedure can also treat any point going to the root of the matter such as one pertaining to jurisdiction or maintainability as a preliminary point and can dismiss a suit without proceeding to record evidence and hear elaborate arguments in the context of such evidence, if the Court is satisfied that the action would terminate in view of the merits of the preliminary point of objection.*

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448 / 2004 उनवान *Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner* में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to <u>keep out of courts irresponsible law suits.</u> Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised.*

<u>Role of the Court/Judge</u>

10. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत न्यायालय / न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान T. Arivandandam vs T. V. Satyapal & Another में दिनांक 14.10.1977 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत न्यायालय / न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The learned Munsif must remember that if on a meaningful-not formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, be should exercise his power under Or. VII r. 1 1 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. <u>An activist Judge is the answer to irresponsible law suits.</u> The trial court should insist imperatively on examining the party at the first bearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code (Ch. XI) is almost forceful enough to meet such men, and must be triggered against them. In this case, the learned Judge to his cost realised when George Bernard Shaw remarked on the assassination of Mahatma Gandhi "<u>It is dangerous to be too good.</u>*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. <u>If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing</u> by examining the party searchingly under Order X of the Code.*

<u>Material to be considered</u>

12. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *<u>At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration</u>. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if <u>the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon,</u> would the same result in a decree being passed.*

<u>Test</u>

13. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. <u>The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.</u>*
>
> *Whether a plaint discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. But whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose, the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. <u>The test is as to whether if the averments made in the plaint are taken to be correct in their entirety, a decree would be passed</u>." In Hardesh Ores (P.) Ltd. v. Hede & Co.5 the Court further held that it is not permissible to cull out a sentence or a passage, and to read it in isolation. It is the substance, and not merely the form, which has to be looked*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

into. The plaint has to be construed as it stands, without addition or subtraction of words.

How to read and examine the plaint

14. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *If on a meaningful reading of the plaint, it is found that the suit is manifestly vexatious and without any merit, and does not disclose a right to sue, the court would be justified in exercising the power under Order VII Rule 11 CPC. 12.9 The power under Order VII Rule 11 CPC may be exercised by the Court at any stage of the suit, either before registering the plaint, or after issuing summons to the defendant, or before conclusion of the trial, as held by this Court in the judgment of Saleem Bhai v. State of Maharashtra.*
>
> *A three-Judge Bench of this Court in State of Punjab v. Gurdev Singh,13 held that the Court must examine the plaint and determine when the right to sue first accrued to the plaintiff, and whether on the assumed facts, the plaint is within time. The words "right to sue" means the right to seek relief by means of legal proceedings. The right to sue accrues only when the cause of action arises. The suit must be instituted when the right asserted in the suit is infringed, or when there is a clear and unequivocal threat to infringe such right by the defendant against whom the suit is instituted.*

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *There cannot be any compartmentalization, dissection, segregation and inversions of the language of various paragraphs in the plaint. If such a course is adopted it would run counter to the cardinal canon of interpretation according to which a pleading has to be read as a whole to ascertain its true import. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction or words or change of its apparent grammatical sense. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. At the same time it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

16. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 330/2010 उनवान *Ram Kripal Das Ji Charitable Trust vs Phool Cha* में दिनांक 29.02.2012 को दिये गये

निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के *सारांश* (Essence) को स्पष्ट किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *11. Before dealing with the factual scenario, the spectrum of Order 7 Rule 11 in the legal ambit needs to be noted. The legal position in regard to Order 7 Rule 11 CPC may be summerised as below:*
>
> *(i) The relevant facts which need to be looked into for deciding an application under Order 7 Rule 11 are the averments made in the plaint. The trial Court can exercise the power at any stage of the suit-before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Order 7 Rule 11 of the Code, the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage.*
>
> *(ii) The basic question to be decided while dealing with an application filed under Order 7 Rule 11 of the Code is whether a real cause of action has been set out in the plaint or something purely illusory has been stated with a view to get out of Order 7 Rule 11 of the Code.*
>
> *(iii) The Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order 7 Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the Code.*
>
> *(iv) For deciding such an application not any particular plea has to be considered, and the whole plaint has to be read. Only a part of the plaint cannot be rejected and if no cause of action is disclosed, the plaint as a whole must be rejected.*
>
> *(v) Rule 11 of Order 7 CPC lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of the written statement. Instead, the word "shall" is used, clearly implying thereby that it casts a duty on the court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the various clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. Even if no objection is taken by the defendant by filing an application under this provision, the court itself is empowered to reject the plaint if it finds that the case is covered within the four corners of this provision.*
>
> *(vi) It is well settled that the question of jurisdiction namely whether a suit is exclusively triable by a revenue court or a Civil Court can take cognizance of it has to be decided on the allegations made in the plaint. It is also further settled that it is the substance of the plaint and the true nature of the suit that is to be seen to determine the question of jurisdiction. If in substance the relief claimed is one which the revenue court alone is entitled to give, the jurisdiction of the civil court will be ousted even though it may require the revenue court to incidentally determine some ancillary facts. In order to determine the true nature of the relief claimed in a suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered. Each case has to be examined on its own particular facts and no universal rule can be applicable to every case.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

17. उपरोक्त विधिक प्रावधान न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत वाद को रेस—ज्यूडिकेटा से संबंधित विधि द्वारा वर्जित बताया गया है। इस संबंध में (Barred by Law) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है।

Barred by Law

18. सर्वप्रथम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *M.Nelson Babu vs K.Kamalesh Babu* में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *11. <u>Order 7 Rule 11(d) has limited application</u>. For its applicability, it must be shown that the present suit is barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction. For the purpose of invoking the said provision, no amount of evidence can be looked into.*

19. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Dega Jayalakshmi & Others Vs. Kapoor Enterprises* में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Law within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well.*

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3460 / 2000 उनवान *Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association* में दिनांक 29.08.2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *Clause (d) of Order VII Rule 7 speaks of suit, as appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Disputed questions cannot be decided at the time of considering an application filed under Order VII Rule 11 CPC. Clause (d) of Rule 11 of Order VII applies in those cases only where the statement made by the plaintiff in the plaint, without any doubt or dispute shows that the suit is barred by any law in force.*

21. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Balachandra Builders Vs. Anis and others* में दिनांक 01.03.2017 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

> *24. Yet another contention [illegible] ned counsel for the applicant/original 6th defendant is [illegible] the suit has to be rejected on the ground of limitation. According to the learned counsel though plea of limitation is generally mixed question of law and facts, when the suit itself [illegible] led beyond the period of limitation, as specifically provided, the suit should be rejected under Order 7 Rule 11 (d), 7 and 8 CPC. In support of his*

contention, the learned counsel relied on the judgment reported in wherein the Hon'ble Apex Court in paragraph No.25 and 41 held as follows:

"25.The language of Order 7, Rule 11, C.P.C. is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the Suit appears from the statement in the Plaint to be barred by any law. Mr.Nariman did not dispute that "law" within the meaning of clause (d) of Order 7, Rule 11 must include the law of limitation as well. It is well settled what whether a Plaint discloses a cause of action is essentially a question of fact, but whether it does or does not must be found out from reading the Plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is whether the averments made in the Plaint, if taken to be correct in their entirety, a decree would be passed. The averments made in the Plaint as a whole have to be seen to find out whether clause (d) of Rule 11 of Order 7 is applicable. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction of words or change of its apparent grammatical sense. As observed earlier, the language of clause (d) is quite clear but if any authority is required, one may usefully refer to the judgments of this court in Liverpool & London S.P. & I Assn. Ltd. v. M.V. Sea Success I and Popat and Kotecha Property v. state Bank of India Staff Assn.

22. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Kasthuri and others Vs. Baskaran and another* में दिनांक 22.08.2003 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

19. It is settled law as held by various Courts that where on the face of the plaint, a suit appears to be barred by any law, the Court shall dismiss the suit. But where it does not so appear, but requires further consideration or, in other words, if there be any doubt or if the Court is not sure and certain that the suit is barred by some law, the Court cannot reject the plaint under Clause (d) of Order 7 Rule 11 of C.P.C.

20. In this context, it would be relevant to quote the observation made by the Bombay High Court in A.I.R.1999 Bombay 161 (supra), with which I entirely agree. The observation is as follows:

"It is settled law that the plaint can be rejected as disclosing no cause of action if the Court finds that it is plain and obvious that the case put forward is unarguable. The phrase "does not disclose a cause of action" has to be very narrowly co ued. Rejection of the plaint at the threshold entails very serious consequences for the plaintiff. This power has, therefore, to be used in exceptional circumstances. The Court has to be absolutely sure that on a meaningful reading of the plaint it does not make out any case. The plaint can only be rejected where it does not disclose a cause of action or where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any provision of the law. While exercising the power of rejecting the plaint, the Court has to proceed with utmost caution. This power ought to be used only when the Court is absolutely sure that the plaintiff does not have a arguable case at all. The exercise of this power though arises in civil procedure, can be said to belong to the realm of criminal jurisprudence and any benefit of the doubt must go to the plaintiff, whose plaint is to

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

be branded as an abuse of the process of the Court. This jurisdiction ought to be very sparingly exercised and only in very exceptional cases. The exercise of this power would not be justified merely because the story told in the pleadings was highly improbable or which may be difficult to believe."

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4766/2001 उनवान *Ramesh B. Desai and Others Vs. Bipin Vadilal Mehta and Others,* में दिनांक 11.07.2006 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

The plaint without addition or subtraction must show that it is barred by any law to attract application of Order 7 Rule 11 CPC. The principle is, therefore, well settled that in order to examine whether the plaint is barred by any law, as contemplated by sub-rule (d) of Order VII Rule 11 CPC, the averments made in the plaint alone have to be seen and they have to be assumed to be correct. It is not permissible to look into the pleas raised in the written statement or to any piece of evidence.

24. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Chandra Vs. Reddappa Reddy* में दिनांक 10.06.2011 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

When a part of the relief sought for in the plaint is within time and even if another part of the relief sought for in the plaint is barred by limitation, a plaint cannot be rejection in part. A plaint cannot be rejected in part is a well settled proposition of law. Therefore, the trial court is right in rejecting the application. Further, it has to be pointed out that it is also well settled that the question of limitation is a mixed question of law and fact and therefore that has to be decided only on the basis of the evidence adduced in the trial and therefore the trial court is right in rejecting the application.

25. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 2517/2007 उनवान *Hardesh Ores Pvt. Ltd vs M/S. Hede And Company* में दिनांक 15.05.2007 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उपबन्ध—डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

21. The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Mr. Nariman did not dispute that "law" within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well. It is well settled that whether a plaint discloses a cause of action is essentially a question of fact, but whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is whether the averments made in the plaint if taken to be correct in their entirety a decree would be passed. The averments made in the plaint as a whole have to be seen to find out whether clause (d) of Order VII is applicable. It is not permissible to read out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction of words or change of its apparent

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

grammatical sense. As observed earlier, the language of clause (d) is quite clear but if any authority is required, one may usefully refer to the judgments of this court in Liverpool & London S.P. & I Association Ltd. Vs. M.V. Sea Success I and another : (2004) 9 SCC 512 and Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association : (2005) 7 SCC 510.

26. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिवचन किया है कि उक्त दावे में सरकारी संस्था ग्राम पंचायत के पक्षकार होने पर तथा दावे में वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 के तहत सरकारी संस्था ग्राम पंचायत को बिना नोटिस दिये हस्तगत वाद दायर किया है। जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 के तहत सरकारी संस्था को दो माह का नोटिस देना आवश्यक कानूनी बाध्यता है। उक्त कानूनी बाध्यता की पालना नहीं होने पर दावा विधि द्वारा वर्जित है। अतः वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिले—ए—खारिज है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है—

80. Notice.— *Save as otherwise provided in sub-section (2), no suits **shall** be instituted against the Government (including the Government of the State of Jammu and Kashmir) or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity, until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to, or left at the office of*

(a) in the case of a suit against the Central Government, except where it relates to a railway] a Secretary to that Government;

(b) in the case of a suit against the Central Government where it relates to railway, the General Manager of that railway;

(bb) in the case of a suit against the Government of the State of Jammu and Kashmir, the Chief Secretary to that Government or any other officer authorized by that Government in this behalf;

(c) in the case of a suit against any other State Government a Secretary to that Government or the Collector of the district; and, in the case of a public officer, delivered to him or left at his office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims; and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

27. उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 के प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी सरकारी संस्था या किसी सरकारी अधिकारी के विरूद्ध बिना दो माह की अवधि का नोटिस दिये बिना किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 में ''**Shall"** का होना प्रावधान को अपरिहार्य बनाता है। जिसकी पालना करना न्यायालय की जिम्मेदारी है एवं न्यायालय के पास कोई अन्य विकल्प व विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम—1994 की धारा—109 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है—

109. Suits etc., against Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad.- *(1) No suit or other civil proceeding against a Panchayati Raj Institution or against any member, officer or servant thereof or against any person acting under the direction of a Panchayati Raj Institution or any member, officer or servant thereof for anything [purporting to be done under this Act in its or his official capa*

*(a) **shall** be instituted until the expiration of two months, after notice in writing, stating the cause of action, the name and place of adobe of the intending plaintiff and the nature of the relief which he claims, he has been delivered or left at its office or in the case of a member, officer, servant or person as*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested

aforesaid delivered to him or left at the office or at his usual place of abode, and he plaint shall in each such case contain a statement that such notice has been so delivered or left, or
(b) shall be instituted, unless it is a suit for the recovery of immovable property or for a declaration of title thereto, otherwise than within six month after transfer next the accrual of the alleged cause of action.
(2) The notice referred to in Sub-sec. (1), when it is intended for a Panchayat, Panchayat Samiti or a Zila Parishad, shall be addressed to the Sarpanch, Vikas Adhikari or the Chief Executive Officer respectively.

28. उक्त राजस्थान पंचायती राज अधिनियम—1994 की धारा—109 के प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी सरकारी संस्था या किसी सरकारी अधिकारी के विरूद्ध बिना दो माह की अवधि का नोटिस दिये बिना किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम—1994 की धारा—109 में ''**Shall"** का होना प्रावधान को अपरिहार्य बनाता है। जिसकी पालना करना न्यायालय की जिम्मेदारी है एवं न्यायालय के पास कोई अन्य विकल्प व विवेकाधीन शक्ति नहीं है।

29. प्रकरण में वादी द्वारा हस्तगत वाद को हाजा न्यायालय में संस्थगित करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम—1994 की धारा—109 के उक्त विधिक प्रावधान के अनुसार कोई नोटिस दिया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज / नोटिस की तामिल पत्रावली पर शामिल नहीं की है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो एवं विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—80 के उक्त विधिक प्रावधान की कानूनी बाध्यता पूरी नहीं होने के आधार पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दावा खारिज किया है।

उक्त निर्णय आज 17.10.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.23 21:15:47 IST
Reason: SelfAttested